वर्ष 1 अंक 10 अक्तूबर 1979 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

आओ हम एकजुट होकर मैदान में कूद पड़ें

मध्यावधि संसदीय चुनाव सत्ता के लिए संघर्ष होगा जिसमें विरोधी बुर्जुआ गठजोड़ कहीं तक भी गिर सकता है. राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात यह जाहिर करती है कि बुर्जुआ लोकतंत्र के कोई भी तौर तरीके नहीं अपनाए जाएंगे. पहले ही भारतीय चुनावों की प्रवृति हिंसा की ओर है, हाल ही के बिहार पंचायत चुनाव में 50 से कम जानें नहीं गयीं हैं. अभी तक, गोली चलाना, चुनाव बूथों पर कब्जा कर लेना, दूसरों को वोट देने से जबरदस्ती रोकना केवल स्थानीय घटनाएं ही थीं न कि चुनाव परिणामों को बदलने के लिए दूर तक फैले षडयंत्र के तरीके. पश्चिम बंगाल में 1972 के चुनावों के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस ने मास रिगिंग शुरू की. अब बुर्जुआ-जमींदार पार्टियों में संघर्ष चरम सीमा पर पहुंच रहा है और यह बिल्कुल मुमकिन है कि आगामी चुनावों में इन तरीकों का दूर दूर तक जबरदस्त इस्तेमाल किया जाए, कई राज्यों में राजनीतिक दलों के समर्थकों में चुनावों का स्थायी झगड़ा बनना मुमकिन हैं.

यह मौजूदा प्रणाली के राजनीतिक-आर्थिक संकट की गंभीरता को और बुर्जुवा-जमींदार पार्टियों के सरकारी मशीनरी हथियाने में युद्ध जैसे मतभेदों को दर्शाता है.

यह मतभेद संसदीय चुनावों तक ही सीमित नहीं रहने जा रहा है. लगता है कि कई राज्यों में भी चुनाव होने की संभावना है. आसाम, यू. पी., बिहार की राज्य विधान सभाओं के लिए भी मध्यावधि चुनाव होना मुमकिन है. गुजरात में तो पहले ही चुनाव होने हैं. समूचा देश बड़े राजनीतिक संघर्ष में एक बार फिर मंथा जाना है.

मौकापरस्त अपीलों से सावधान

इस स्थिति में, वोट खींचने के इरादों से मौकापरस्त अपीलों की संभावना है. अगर किसानों और ग्रामीणों को रक्षा के नाम पर किसानों को मजदूर वर्ग व अन्य दलितों के खिलाफ किया गया तो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुसेवा होगा. भारत का भविष्य किसानों व मजदूरों के मेलजोल पर निर्भर करता है और ऐसी कोई भी अपील, जो इसे भंग करती हो, प्रतिक्रियावाद की ताबेदारी के अलावा और कुछ नहीं कही जा सकती.

पिछला संसद इमरजेंसी के अत्याचार से सचेत होकर और तानाशाही की ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए चुना गया था. जनवाद या तानाशाही का नारा इंदिरा गांधी विरोधी सभी पार्टियों का आम संग्रामी नारा था. लेकिन जनता पार्टी शुरू के प्रशंसनीय कदमों—प्रेस की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों को बहाल करने, 42वें संशोधन कानून से संबंधित—के बाद संघर्ष को आगे बढ़ाने में नाकामयाब रही. लेकिन 42वें संशोधन कानून

बी. टी. रणदिवे

की सभी शरारतों को खत्म नहीं किया गया. जनता नेताओं ने कांग्रेस (इं) के साथ समझौता करना ही चुना बजाए इसके कि वह राज्य सभा में खिलाफ वोटों का सामना करती और इसके तानाशाही चेहरे को जनता के सामने बेनकाब करती. जनता पार्टी ने, जो अन्य किसी भी बुर्जुवा-जमींदार पार्टी की तरह काम कर रही थी, जन समर्थन को और अधिनायकवाद की ताकतों

[शेष पृष्ठ चार पर]

हड़ताली कपड़ा मजदूरों के समर्थन में
11 अक्तूबर को दिल्ली बंद

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ कनवेंशन

4 अगस्त को आंध्र प्रदेश मैडिकल एण्ड सेल्स रिप्रेजेंटिटिव्स एसोसिएशन ने ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ हैदराबाद में एक ट्रेड यूनियन कनवेंशन बुलाया. इस कनवेंशन में हैदराबाद की फार्मेस्यूटीकल्स वर्कर्स की विभिन्न यूनियनों की ओर से 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें ए. पी. एम. एस. आर. के., साउथ इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिरिस), आई. डी. पी. एल., बाया कैमिकल्स एण्ड सिंथैटिक लैबोरेट्रीव आदि की यूनियनें शामिल थीं. सीटू, एच. एम. एस., बी. एम. एस.—तीनों ट्रेड यूनियनें तथा और दूसरी यूनियनें इस कनवेशन में शामिल हुईं.

प्रस्ताव

मुख्य प्रस्ताव में बताया गया था कि किस तरह फार्मेस्यूटीकल्स उद्योगों में ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं को दंडित करने की नीति अपनाई जाती है. प्रस्ताव में सिरिस के प्रबंधकों के मजदूर विरोधी रवैये का भंडाफोड़ था जिसका मैनेजिंग डाइरैक्टर इंदिरा कांग्रेस का है, जिसने हैदराबाद तथा विजयवाड़ा की कंपनियों से 150 मजदूरों को सिर्फ इसलिए निकाल दिया है क्योंकि उन लोगों ने अपने हितों की रक्षा के लिये वहां पर यूनियन बनाई थी. एक साल से ये मजदूर वहां अपना शानदार संघर्ष चला रहे हैं. इस संस्थान के संघर्षरत मजदूरों को अपनी एकजुटता और समर्थन देने का आह्वान करने के साथ-साथ इस कनवेंशन ने चेन्ना रेड्डी सरकार की इस बात पर कड़ी आलोचना की कि वह इस संस्थान के मैनेजमेंट के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा रही.

सीटू द्वारा समर्थन

कनवेंशन में बोलते हुए, मैडीकल रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया के फेडरेशन के सचिव ने बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किये जाते शोषण के अनेक तरीकों का भंडाफोड़ किया जो हमारे दवाई-औषधि उद्योग में देशी इजारेदारों के साथ 80% उत्पादन का नियंत्रण करते हैं. उन्होंने सरकार की इस बात पर आलोचना की कि उसने हाथी कमेटी की दवाओं व औषधियों के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों का राष्ट्रीयकरण की सिफारिश को नहीं माना. उन्होंने एफ. एम. आर. ए. जे. द्वारा सिरिस के संघर्षरत मजदूरों को अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया. आंध्र प्रदेश सीटू स्टेट कमेटी के सचिव एन. पी. भास्कर राव ने कनवेंशन में बोलते हुए संघर्षरत मजदूरों को सीटू की ओर से पूरा समर्थन देने का आश्वा- दिया और आह्वान किया कि अपने संघर्ष को आगे ले जायें.

ए. पी. एम. एस. आर. ए. तथा आंध्र प्रदेश फार्मेस्यूटीकल एम्प्लाईज कोआर्डिनेशन कमेटी ने राज्य के विभिन्न स्थानों में ऐसी ही कनवेंशन आयोजित करने का निर्णय किया है और शीघ्र ही विजयवाड़ा में एक कनवेंशन बुलाया जाएगा.

पटना

बंगलौर कनवेंशन जैसा ही एक कनवेंशन पटना में आयोजित किया गया. इसे ऑल इंडिया केमिकल एण्ड फार्मेस्यूटीकल इंडस्ट्री (ए. आई. सी. ए. पी. ई. एफ.) की बिहार शाखा ने 19 अगस्त 1979 को किया जिसमें सर्विस एसोसियेशन और फेडरेशन से संलग्न 35 विभिन्न यूनियनों से एक हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इनमें ए. आई. सी. ए. पी. ई. एफ. (बिहार) और एफ. एम. आर. ए. आई. (पश्चिम बंगाल) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया.

ए. आई.सी. ए. पी.ई .एफ. (बिहार) के अध्यक्ष पी. के. गांगुली ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बहुराष्ट्रीय निगमों का दवा और औषधि क्षेत्र के उद्योगों में खासकर और भारतीय अर्थव्यवस्था में आमतौर पर बढ़े हुए नियंत्रण की चर्चा की. सी. एस. शर्मा ने प्रस्तावर रखते हुए ड्रग कार्टेलों द्वारा कर्मचारियों को दंडित किए जाने की चर्चा की और बताया कि एफ. एम. आर. ए. आई. तथा उससे संबंद्ध यूनियनों के कार्यकर्त्ताओं को नौकरी से निकाला जा रहा है.

ए. आई. सी. ए. पी. ई. एफ. और एफ. एम. ए. आई. के महासचिव जे. एस. मजूमदार ने बताया कि किस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां घांधली करती

[शेष पृष्ठ बारह पर]

चीन को शुभकामनाए

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज और सीटू मजदूर चीन के मजदूर वर्ग और जनता को चीनी क्रांति की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर हार्दिक बधाई देता है.

सीटू चीन की जनता व मजदूर वर्ग को समाजवादी निर्माण में, विज्ञान तथा औद्योगिक उन्नति में शानदार उपलब्धियां हासिल करने के लिए बधाई देती है.

सीटू यह आशा करती है कि आने वाले दिनों में भारत और चीन के बीच संबंध जीवन के हर क्षेत्र में लगातार अच्छे होते रहेंगे.

सीटू आल चाइना फेडरेशन आफ लेबर को हार्दिक बधाई भेजती है तथा उनकी सभी कार्यवाहियों में पूर्ण सफलता की कामना करती है. *

11 अक्तूबर को दिल्ली बंद

इस 27 सितंबर से दिल्ली कपड़ा मजदूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को चौथा महीना लग चुका है. प्रबंधकों के हिमायती 'दिल्ली प्रशासन' ने 11 सितंबर को कपड़ा प्रबंधकों की सेवा के लिए, इस विवाद को एड्ज्यूडिकेशन (न्यायिक निर्णय) को सौंप दिया.

भारी वर्षा के बावजूद अगले दिन 5 कपड़ा मिलों के सात हजार कपड़ा मजदूर शहर में यह शपथ लेने के लिए इकट्ठा हुए कि विवाद को ट्रिब्युनल में सौंप देने के बावजूद हड़ताल जारी रहेगी.

कपड़ा मजदूरों की एक्शन कमेटी द्वारा आयोजित सभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें कहा गया है कि *"दिल्ली प्रशासन ने यह कार्रवाई प्रबंधकों तथा केंद्रीय सरकार के दबाव में आकर की है जो कि अविवेकशील, अविचारणीय तथा तथा बेईमानी है"* कमेटी ने यह आरोप लगाया कि दिल्ली में जीवन निर्वाह सूचकांक के हिसाब में धोखाधड़ी को केंद्रीय सरकार द्वारा आसानी से ठीक किया जा सकता है, इस बात का ट्रिब्युनल को बिल्कुल भी विवरण नहीं दिया गया.

सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने अपने संक्षिप्त भाषण में कपड़ा मजदूरों को अपनी दृढ़ता, चट्टानी एकता तथा हड़ताल को बरकरार रखने में बलिदान की भावना के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि आजादी के 32 सालों के बाद भी मजदूरों को अपनी जायज मांगों के लिए ऐसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है. उन्होंने दिल्ली प्रशासन तथा केंद्रीय सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह इन सवालों को ठीक ढंग से तथा जल्द से जल्द निबटाने की कोशिश नहीं कर रही.

इस दौरान अधिकतर राजनैतिक दलों ने हड़ताली कपड़ा मजदूरों को हर तरह से सहायता देने का आश्वासन दिया है. 19 सितंबर को सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल के समर्थन में सामूहिक जन धरने, प्रदर्शन और जनसभाएं तथा कपड़ा मिलों से संबंधित सभी फुटकर दुकानों की पिकेटिंग इत्यादि करने की योजना बनाई है.

बैठक ने 11 अक्तूबर को दिल्ली बंद का आह्वान किया है. कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक संयोजक समिति का गठन किया गया है जिसमें सीटू की नुमाइदगी दिल्ली सीटू के महासचिव जयन्त राय कर रहे हैं. *

जल कर्मचारियों का धरना समाप्त

दिल्ली म्युनिसिपल वर्कर्स लाल झण्डा यूनियन (सीटू) ने म्युनिसिपल कार्पोरेशन के दफ्तर के सामने से दो महीने से चले आ रहे धरने को मेयर के इस आश्वासन पर वापस ले लिया है कि मजदूरों को किसी भी प्रकार से विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा और प्रदर्शन के संबंध में डिसमिस किए गए सभी मजदूरों को वापस ले लिया जाएगा सिवाय उनके जिन पर तोड़फोड़ के आरोप हैं. याद रहे कि दो महीने लम्बे इस आंदोलन में लगभग 500 स्थायी कर्मचारियों को विक्टिमाइज किया गया था तथा अन्यों को विक्टिमाइज करने की धमकियां दी गई थीं. *

सीटू द्वारा मध्य प्रदेश में पुलिस अत्याचारों का विरोध

सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति, संसद सदस्य, ने 22 सितंबर को मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री श्री वी. के. सकलेचा को निम्नलिखित पत्र लिखा, जिसे प्रेस को जारी किया जा रहा है.

यह जानकर गहरा दुख हुआ कि राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को रेवा में सभाओं में बोलने से रोका जा रहा है तथा उनकी सभाओं पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमले किए जा रहे हैं जिन्हें पुलिस खुले आम प्रोत्साहित कर रही है तथा उनका खुद का भी उनकी पिटाई करने में हाथ है.

मैं 'दैनिक भास्कर' में 19 सितंबर को छपी एक खबर भेज रहा हूं जिसमें यह विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से 16 सितंबर को प्रख्यात नेता तथा सी.पी.आई.(एम) के सदस्य श्री ब्रजेन्द्र पाण्डेय को एक कोतवाल के हाथों सिर में चोटें आईं. ऐसी घटना का उस समय घटना जदकि डी. आई. जी. को ऐसा होने की सूचना पहले ही दे दी गई हो यह और भी खेद की बात है. इस घटना से हमारे संविधान के 'भाषण की स्वतंत्रता' के बुनियादी अधिकार के क्रूरता से कुचल डालने की बू आती है. यह तथ्य कि एक ए. एस. आई. का गिरफ्तार कर लिया जाना तथा उस कोतवाल का जिसका नाम श्री पाण्डेय ने लिया था, आम लोगों को डराते हुए सरेआम घूमना, यह दिखाता है कि पुलिस उच्चाधिकारी मुजरिम को पनाह दे रहे हैं.

मैं इसलिए इसके खिलाफ अपना विरोध प्रकट करता हूं तथा आपसे इस घटना की सी. बी. आई. द्वारा तुरंत जांच तथा दोषी पुलिस अफसर को दंड देने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं. अगर आप इस बारे में उठाए गए कदमों की जानकारी मुझे दे सकें तो मैं आपका आभारी हूंगा. *

के खिलाफ संघर्ष के लिए जन गतिविधि को खो दिया तथा अपने फैसले करने के लिए इंदिरा द्वारा प्रशिक्षित ब्यूरोक्रेसी पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया. जनता को एकजुट करने की अगुवाई इंदिरा गांधी पर छोड़ दी गई. शाह कमीशन, इस द्वारा भंडाफोड़, विशेष अदालतें—सभी जल्दी ही सरकार के वह काम बन गये जिनमें जनता की कोई भागीदारी नहीं थी.

जनता पार्टी का बदला चेहरा

जनता पार्टी द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रियावादी होती गईं और यह बदनाम जबरन जमा योजना को एक अध्यादेश द्वारा लागू करने से चरम सीमा पर पहुंच गयी—जबरन जमा योजना जिसमें इमरजेंसी की बदबू थी. जनता सरकार अपने अधिनायकवादी झुकाव दर्शाने लगी. मोरारजी ने केंद्र में निवारक नजरबंदी कानून लागू करने की इच्छा जाहिर की और पुलिस कर्मियों का आंदोलन का दमन इतनी क्रूरता के साथ किया गया जितनी क्रूरता के साथ इंदिरा गांधी के शासन में होता था.

यह सब इस बात का प्रतीक थे कि अधिनायकवाद और तानाशाही की ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए जनता द्वारा बनाया गया हथियार टूट रहा था. इसका खतरा बढ़ता जा रहा था कि जनता अपने ही हथियार द्वारा ही मारी जाएगी.

लोक सभा का भंग होना और चुनावों का होना एक बार फिर यह सवाल पैदा करते हैं—कि इंदिरा गांधी की तानाशाही की ताकतों के खिलाफ कैसे लड़ा और उन्हें पराजित किया जाए, जनता पार्टी के विघटन के बाद पैदा हुई स्थिति का फायदा उठाकर सत्ता हथियाने की असली कोशिशों को कैसे धराशायी किया जाए.

लेकिन जनता पार्टी के प्रभुत्वशाली नेतृत्व ने संगठन की एकता को तोड़ते हुए एक बार फिर जबरदस्त समस्या खड़ी कर दी. संगठन और सरकार दोनों ही ज्यादा से ज्यादा आर. एस. एस.-जनसंघ के नियंत्रण और प्रभुत्व में होते चले गए. जनता में आंतरिक लड़ाई मोरारजी की मदद से आर. एस. एस. जनसंघ द्वारा केंद्रीय सरकार में प्रभुत्वशाली स्थान हथियाने और दूसरों को सत्ता से बाहर करने के लिए लड़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं थी. इस दल का कई राज्यों की सरकारों पर पहले ही नियंत्रण था. इसने यू. पी., बिहार, हरियाणा की जनता सरकारों को गिराने का खेल शुरू किया और बिहार व हरियाणा में इसको कामयाबी मिली. सांप्रदायिक ताकतों द्वारा केंद्रीय सरकार को हथिया लेने का खतरा दिखाई देने लगा.

जनता पार्टी का प्रभुत्वशाली नेतृत्व इंदिरा गांधी की अधिनायकवादी ताकतों की बजाए पार्टी के अंदर धर्म निरपेक्ष और जनवादी ताकतों से लड़ने के लिए ज्यादा उत्सुक था.

आर.एस.एस. गठजोड़ का असली राजनीतिक अर्थ

इसके अलावा, सांप्रदायिक हिंदू उग्र राष्ट्रवाद शब्द आर. एस. एस.-जनसंघ गठजोड़ के वास्तविक राजनीतिक मतलब को को नहीं दर्शाता है. यह मुसलमानों और दूसरे गैर-हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक मानता है और ये हिंदुओं के समान स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं. समान स्थान पाने के लिए उनको बहुमत संप्रदाय में मिल जाना होगा.

इसके अलावा आर. एस. एस. हिंदुओं में क्रूर जातिप्रथा का जबरदस्त समर्थक है जो "निम्न जाति" वालों को तुच्छ स्थान देता है और ऊंची जातियों के प्रभुत्व को मानता है.

गोलवलकर द्वारा इस पद्धति की प्रशंसा पर गौर कीजिए जो हमारे करोड़ों लोगों पर छूआ-छूत थोंपता है. *"इतिहास सिद्ध करता है कि मुसलमान उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी इलाकों को, जहां बुद्धधर्म ने जाति प्रथा को तहस-नहस कर दिया था, जीत सकता था·····लेकिन इसके विपरीत. दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के शासन के बावजूद हिंदू धर्म मजबूत था क्योंकि वहां जाति प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता था"* **(बंच आफ थाट्स)**. और फिर, *"कुछ लोग इसकी मौजूदा पिशाची बिगड़ाव के कारण जाति प्रथा का विरोध करते हैं. उनका विश्वास है कि पीढ़ि दर पीढ़ि हमारा अपमान जाति प्रथा के कारण ही हुआ है. लेकिन असलियत में क्या यह इतिहास द्वारा साबित हुआ है. जाति प्रथा पुराने जमाने में थी. और हम अपनी चरम सीमा पर थे. कोई भी ऐसी बात नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि इसने हमारे सामाजिक विकास में बाधा डाली है. असलियत में जाति प्रथा ने हमारे समाज की एकता को बनाए रखने में मदद की है."* **(बंच आफ थाट्स)**.

इसके तहत किस प्रकार का राजनीतिक जनवाद मुमकिन है ? यह जाति-विशेषाधिकारों तथा कुछ ऊंची जातियों के पक्षपातों से सामाजिक समर्थन देने की अपील करते हुए अधिनायकवाद की एक और किस्म के अलावा कुछ भी नहीं होगा. इस चुनौती का निम्न-आंकन किया जा रहा है. इस बात को महसूस नहीं किया जा रहा है कि जनता पार्टी के दिखावटी रूप के पीछे सांप्रदायिक तथा जातिवादी ताकतें केंद्रीय सरकार को हथियाने में करीब करीब सफल हो गईं थीं.

मजदूर वर्ग की भूमिका

आगामी क्रांतिक चुनावों में अपनी भूमिका निभाने के लिए मजदूर वर्ग और कर्मचारी आंदोलन का फिर से आह्वान किया जा रहा है. 1977 के चुनावों में, इसने बिना किसी झिझक के इमरजेंसी के खिलाफ सभी ताकतों के साथ एकजुट होकर काम किया तथा अधिनायकवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने में मदद की.

[शेष पृष्ठ तेरह पर]

तमिलनाडु

काले अध्यादेश वापस लो

जनता सरकार के रिजर्व बैंक संबंधी अध्यादेशों से उत्साहित होकर तमिलनाडु सरकार ने यह कहते हुए कि अनिवार्य सेवाओं में हड़तालों से ठीक तरह से निबटने के लिये वर्तमान कानून नाकाफी हैं, 13 जुलाई और 22 अगस्त को दो अध्यादेश जारी कर दिये जो मौजूदा औद्योगिक कानूनों के संशोधनों के रूप में पेश किये गये.

दंड नीति

पहला अध्यादेश सरकार को यह शक्ति दे देता है कि वह समझती है कि किसी उद्योग में होने वाली हड़ताल समाज के अहित में है तो वह उस पर रोक लगा सकती है. इस अध्यादेश के अनुसार अधिकारियों से पूर्व स्वीकृत छुट्टी लेकर यदि कोई हड़ताली ड्यूटी पर नहीं आता तो उसका यह काम गैरकानूनी माना जायगा. 'धीरे काम करो' गैर कानूनी और दंडनीय बताया गया है. अध्यादेश का सैक्शन 4 कहता है कि यदि अध्यादेश के तहत घोषित गैर कानूनी हड़ताल में कोई मजदूर हिस्सा लेता है तो उसे एक साल की सजा और 2000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है. जो लोग मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहेंगे उन्हें भी एक साल की सजा और 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है. यदि कोई मजदूरों को आर्थिक या अन्य सहायता देता है तो उसे भी वैसा ही दंड मिलेगा. पुलिस अफसरों को अबाध अधिकार दिये गये हैं. मात्र संदेह पर वे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं.

अधिकारों का खात्मा

दूसरा अध्यादेश पहले का पूरक है जिसका उद्देश्य 'औद्योगिक शांति' और अनुशासन की स्थापना करने के साथ-साथ उत्पादन व वितरण की सुरक्षा करना है जिन्हें समाज के लिये जरूरी समझा गया है. यह अध्यादेश मालिकों (?) व मजदूरों (!) दोनों को ही औद्योगिक विवाद कानून के तहत पंच-फैसले को सौंप दिये गये किसी भी विवाद में सरकार की ओर से निश्चित किये गये "कायदे" से चलने को कहता है. अध्यादेश के शुरू में सामाजिक जरूरतों औद्योगिक शांति आदि के बारे में बड़े जोर शोर से चर्चा की गई है और मालिक और मजदूरों को एक ही जगह रखकर धोखा देने की कोशिश की गयी है जिससे कि अध्यादेश का मालिक परस्त चेहरा बेनकाब न हो.

दुनाली बंदूक

ये अध्यादेश सिर्फ हड़तालों को गरकानूनी करार देने तथा मजदूरों की सौदेबाजी की ताकत को सीमित करके उन पर अपने अनिवार्य फैसले थोप देने की दिशा में एक कदम हैं. अन्नाद्रमुक सरकार ने जिसने सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई है जो औद्योगिक कानूनों में संशोधनों पर विचार करेगी—इस सिलसिले में कमेटी से सलाह मशविरा तक नहीं किया यहां तक कि राज्य श्रमिक सलाहकार बोर्ड को सूचना देने की औपचारिकता तक नहीं निबाही गई. ये अध्यादेश संगठित श्रमिक जनता पर तनी हुई दुनाली बंदूक की तरह हैं.

तथाकथित समान बर्ताव

किसी की पुरानी पूंजीवादी सरकार की तरह तमिल सरकार ने मालिक व मजदूरों को एक ही जगह रखकर ऐसा छलावा करने का पुराना हथकंडा अपनाया जैसे वह कई वर्गों से ऊपर कोई चीज हो जबकि इस समझ को 200 वर्ष पुराने ट्रेड यूनियन आंदोलन ने तहसनहस कर दिया है. अनुभव बताते हैं कि ऐसे

[शेष पृष्ठ ग्यारह पर]

मध्य प्रदेश

ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ता आठ जिलों से बाहर निकाला गया :

सीटू ने आई. एल. ओ. को शिकायत भेजी

बांकी कोलियरी सुराकछार, मध्यप्रदेश में कोयला श्रमिक संघ (सीटू) के एक पदाधिकारी नंदलाल को राज्य सरकार ने बिलासपुर तथा अन्य सात लगे हुए जिलों से बाहर ही बाहर रहने का आदेश 7 अगस्त 1979 को दिया जो जिलाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश जन सुरक्षा कानून के सैक्शन 4 के अंतर्गत दिया गया है. इससे पहले 11 दिसंबर 78 को नंदलाल को कारण बताओ नोटिस दिया गया था जिसमें पूछा गया था कि क्यों न उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जाये.

नंदलाल के खिलाफ कुल 25 आरोप लगाये गए जो चार प्रकार के हैं : (1) कि नंदलाल ने प्रदर्शन, बैठकें और हड़तालें कराईं (जोकि एक सामान्य ट्रेड यूनियन कार्य है) (2) कुछ ऐसे आरोप भी थे जिनमें कहा गया था कि उसने दूसरों पर हमले किये (किंतु नंदलाल को अदालत ने बरी कर दिया था क्योंकि कुछ भी साबित नहीं हो सका), (3) कुछ ऐसे आरोप भी हैं जो कि नंदलाल द्वारा दूसरों पर किये गये हमलों से संबंधित हैं और (4) जो मामले अदालत में हैं (इसमें दिलचस्प यह है कि अभी तक कोर्ट में ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं हुआ है) आदि.

जाहिर है कि नंदलाल के खिलाफ लगाये गये आरोप बिलकुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं. कोयला खानों के मालिक अपने लिये असामाजिक तत्वों को किराये पर रखते हैं ओर आये दिन ट्रेड यूनियन करने वाले नेताओं के खिलाफ झूठे केस बनाते रहते हैं. रानीगंज और धनबाद कोयला क्षेत्रों में कुछ नेताओं की हत्या तक कर दी गई है.

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

छत्तीसगढ़ में सीटू यूनियनों की मीटिंग

छत्तीसगढ़ में सीटू से संबद्ध यूनियनों की एक मीटिंग 27 अगस्त को भिलाई गेस्ट हाउस में हुई. म. प्र. सीटू कमेटी के उपाध्यक्ष पी. के. मोइत्रा ने मीटिंग की अध्यक्षता की.

म. प्र. सीटू कमेटी के महासचिव एस. कुमार ने पिछली मीटिंग से अब तक की यूनियनों की गतिविधियों की एक रिपोर्ट पेश की और गतिविधियों में और भी बेहतर तालमेल बैठाने की जरूरत पर जोर दिया.

भिलाई स्टील प्लांट, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि., भिलाई के और पास की लघु उद्योग इकाइयां; राजहरा लौह खान, कोरबा अल्यूमीनियम प्रोजेक्ट, सुराकछार, बांकी, बिसरामपुर चिरमिरी, अमर कंटक, अमलाई की कोयला खानों; बेलाडीला की लौह खनिज खानों की सीटू संबद्ध यूनियनों के प्रतिनिधियों ने उस क्षेत्र में मालिकों व सरकार के आक्रमणों के बावजूद सीटू के लगातार बढ़ते जा रहे काम पर प्रकाश डाला.

मोतीलाल शर्मा ने अपने भाषण में कहा कि संगठन को और मजबूत बना कर ही हम काम को और भी बढ़ा सकते हैं.

सीटू सचिव एम. के. पंधे ने कोयला व इस्पात मजदूरों व सरकार के बीच हाल ही में हुए समझौते की उपलब्धियों की समीक्षा की. उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों के बंगलौर कनवेंशन के फैसलों की व्याख्या की और सभी यूनियनों से एकजुट होकर उन पर अमल करने की अपील की. उन्होंने यूनियनों की सदस्यता बढ़ाने और रोजमर्रा के कामों में सुधार करने पर जोर दिया. उन्होंने सखलेचा सरकार द्वारा सीटू पर किये जा रहे दमन उत्पीड़न की आलोचना की और आस्था प्रकट की कि इन हमलों के बावजूद सीटू आगे बढ़ेगी.

मीटिंग में सीटू की छत्तीसगढ़ रीजनल कमेटी बनाने का निर्णय किया गया जिसमें क्षेत्र में म. प्र. कमेटी में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य भी होंगे. मीटिंग में नंदलाल (बांकी) के राज्य सरकार द्वारा निर्वासन की निंदा और वहां संघर्षरत मजदूरों के संघर्ष के समर्थन में प्रस्ताव पास किया गया. *

कर्नाटक में ट्रेड यूनियन कक्षाएं

कोलार गोल्ड फील्ड में सीटू की कर्नाटक राज्य काउंसिल ने 31 अगस्त व 1 सितंबर को ट्रेड यूनियन कक्षा आरंभ की. ये कक्षाएं स्टेट काउंसिल के सभी सदस्यों के लिये खुली थीं. सीटू के सचिव एम. के. पंधे ने विश्व ट्रेड यूनियन आंदोलन के इतिहास के बारे में बताया. कक्षा में लगभग 100 सदस्यों ने भाग लिया.

आखिरी दिन, एक स्थानीय नाट्य संस्था ने 'मई दिवस' के विषय पर एक नुक्कड़ नाटक किया.

2 व 3 सितंबर को सीटू की कर्नाटक स्टेट काउंसिल की मीटिंग हुई. काउंसिल के महासचिव नंजुंदप्पा ने सीटू के नेतृत्व में चले संघर्षों की समीक्षा की. मीटिंग में इस बात पर भी विचार किया गया कि कमजोर इलाकों में सीटू को कैसे मजबूत बनाया जाय.

2 सितंबर को एक आम सभा की गई जिसका सीटू की तमिलनाडु शाखा के महासचिव ने भी संबोधन किया. *

सीटू की उड़ीसा स्टेट कमेटी ने उड़िया में पत्रिका निकाली

सीटू की उड़ीसा स्टेट कमेटी ने उड़िया भाषा में 'श्रमिक एकता' नाम से एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन सितंबर से शुरू कर दिया है. पत्रिका का प्रकाशन उद्घाटन समारोह उड़ीसा सीटू स्टेट कमेटी के अध्यक्ष शिवाजी पटनायक ने 29 अगस्त को भुवनेश्वर में किया. सीटू के सचिव एम.के. पंधे ने पत्रिका के पहले अंक को विमोचित किया.

उड़ीसा सीटू की स्टेट कमेटी ने उसी दिन अपनी मीटिंग की. शिवाजी पटनायक ने मीटिंग की अध्यक्षता की. स्टेट कमेटी के महासचिव अजय राउत ने पिछली मीटिंग से अब तक की गतिविधियों का मूल्यांकन किया. शिरकत करने वाले सदस्यों ने अपनी गतिविधियों के बारे में और भी विस्तार से बताया. रिपोर्ट से यह जाहिर था कि इन दिनों में राउरकेला, तेन्सा खानों, लघु उद्योगों, रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स तथा पेरा दीप पोर्ट वर्कर्स के बीच हमारी गतिविधियों में विकास हुआ है.

एम.के. पंधे ने विचार विमर्श के दौरान कामरेडों द्वारा उठाई गई समस्याओं के बारे में सीटू की नीतियों की व्याख्या की और राज्य में सीटू की बढ़ती गतिविधियों की संभावनाओं के बारे में बताया.

स्टेट कमेटी ने अगले वर्ष फरवरी में ट्रेड यूनियन-क्लास आयोजित करने का फैसला किया जिसका उद्देश्य अच्छे कार्यकर्ता तैयार करना है. *

मोलिंज मजदूर लगातार हड़ताल पर

मोलिंज इंडिया लिमिटेड के मजदूर सालाना बोनस के सवाल पर 11 अगस्त से हड़ताल पर हैं. हड़ताल में शामिल यूनियनों ने प्रबंधकों की श्रम विरोधी नीतियों की कड़ी निंदा की है और इसके अंग्रेज मैनेजिंग डाइरेक्टर को निकालने की मांग की है. उन्होंने राज्य और इसके श्रम विभाग की भी कड़ी निंदा की है जिन्होंने समझौता कार्यवाहियां किए बगैर ही मुद्दों को औद्योगिक ट्रिब्युनल को सौंप दिया है. अन्य मांगों में मोहाली और कलकत्ता के ट्रेड यूनियन नेताओं के विक्टिमाइजेशन का खात्मा, 20 प्रतिशत सालाना बोनस, जो कि पिछले 12 सालों से चल रहा था, को फिर लागू करना, कलकत्ता के प्रशासकीय स्टाफ से हुए दो समझौतों को पुनः लागू करना और मोहाली इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्रबंधकों की गुंडागर्दी को खत्म करना शामिल है.

राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कोरियाई मजदूर वर्ग का संघर्ष

पिछले दिनों उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच राष्ट्र के शांतिपूर्ण एकीकरण के लिये जो द्विपक्षीय वार्ता कायम हुई थी वह दक्षिणी कोरियाई सरकार के प्रतिकूल रवैये के कारण टूट गयी है. दक्षिणी कोरियाई सरकार ने वार्ता तोड़ने का बहाना लिया कि उत्तरी कोरिया के वार्ता प्रतिनिधि "जिम्मेदार प्रतिनिधि" नहीं हैं जबकि सच्चाई यह है कि उत्तरी कोरिया की ओर का प्रतिनिधि मडल पूरी तरह अधिकारिक और कोरियाई जनवादी जनगणराज्य की सरकार, वर्कर्स पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के नुमाइंदों का था.

यह पहला मौका नहीं जब दक्षिण कोरिया ने आपसी बातचीत में अमरीकी साम्राज्यवादी षड़यंत्रों के अनुरूप बैठने वाले बहाने को लेकर अड़ंगा लगाया हो. दरअसल दक्षिणी कोरिया ने तो शुरू से ही जनता की इस मूल भावना के प्रति बहानेबाजी का रवैया अपनाया है. इसके बावजूद, उत्तरी कोरिया ने लगातार ऐसे उचित प्रस्ताव रखे हैं जो बातचीत में आये तनावों को दूर करने के वास्ते दोनों पक्षों को मंजूर हो सकते हैं.

प्रस्ताव

कोरिया पितृभूमि के एकीकरण के लिये बने जनवादी मोर्चे की केंद्रीय कमेटी ने, हाल ही में, दक्षिणी कोरिया के प्रत्येक जीवन क्षेत्र से, बाहर रहने वाले लोगों तथा सभी राजनीतिक दलों से, जनसंगठनों तथा सरकार से प्रस्ताव किया था कि उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया 4 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य के सिद्धान्तों व आदर्शों पर वापस लौटें और एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछाल बंद करें, एक दूसरे को घृणा करने, धमकाने और सशस्त्र कार्यवाही को बिना शर्त फौरन बंद करें, उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया की सभी पार्टियों, जन संगठनों के प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय कांग्रेस बुलायी जाय.

सीटू इन प्रस्तावों को जो न केवल दुनिया की शांतिप्रिय जनता बल्कि कोरियाई जनता के बीच बहुत ही हमदर्दी और समर्थन पैदा करते हैं तहे दिल से समर्थन करती है. किंतु, दक्षिणी कोरिया ने इन सब चीजों को नजर-अंदाज कर दिया.

दक्षिणी कोरिया सीमांत पर बड़ी दीवार बना रहा है

एक ओर जहां उत्तरी कोरियाई सरकार एकीकरण को लेकर दोतरफा बातचीत के लिए लगातार कोशिश करती रही है, वहीं दक्षिण कोरियाई सरकार-सीमांत रेखा के समांतर एक ठोस दीवार बना रही है. रिपोर्टों के मुताबिक उत्तरी कोरिया के पूरब से पश्चिम तक समूची सीमा की लंबाई में यह दीवार 5 मीटर ऊंची, जमीन में 10 मीटर चौड़ी और चोटी पर 2-3 मीटर चौड़ी है.

दक्षिणी कोरियाई सरकार ने अपने कठपुतली सिपाहियों, जनता के हिस्सों और विभिन्न यंत्रों को इस मुहिम में झोंक दिया है. इसके लिए दक्षिणी कोरिया भारी मात्रा में सीमेंट का आयात कर रहा है क्योंकि अपना उत्पादित सीमेंट कम पड़ गया है.

रिपोर्टें बताती हैं कि दक्षिणी कोरिया ने अब तक दीवार का एक लंबा हिस्सा खड़ा कर दिया है और इन दिनों तेजी से काम चल रहा है. इस तरह तीस साल से विभाजित करने वाली कांटेदार तारों की बाड़ के साथ कंक्रीट की यह दीवार खड़ी की जा रही है.

दक्षिण कोरियाई सरकार ने देश में अमरीकी सेना और विदेशी इजारेदारों की पूंजी को लाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है. उसने अपनी जनता के नौजवानों व मंझली उम्र के लोगों की एक कठतुतली सेना खड़ी की है और उसे सीमा रेखा के साथ-साथ तैनात कर रखा है जिससे कि लगातार तनाव बना रहे और टकराव बढ़ता रहे. मानो यह भी नाकाफी हो—इसलिए अब वह देश को दो हिस्सों में काटकर रखने वाली यह दीवार भी बना रहा है. दक्षिणी कोरिया के इससे पहले के किसी भी शासक ने ऐसा शर्मनाक अभियान कभी नहीं चलाया.

माफ नहीं किया जा सकता

कोरिया देश के प्रति यह एक अक्षम्य अपराध है कि राष्ट्र के एकीकरण की जगह देश के विभाजन को और भी पक्का किया जाय.

किंतु जनरल फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन आफ कोरिया अपने देश की मेहनतकश जनता को अपनी पितृभूमि के एकीकरण के महान उद्देश्य के लिये लगातार तैयार कर रही है.

सीटू की मांग

सीटू दक्षिण कोरियाई सरकार द्वारा कोरिया के विभाजन को इस तरह स्थाई बनाने की कोशिशों की निंदा करती है. सीटू कोरियाई मजदूरों व आम जनता से जो अपने देश के एकीकरण के लिए लड़ रहे हैं—अपनी एकजुटता जाहिर करती है. सीटू मांग करती है कि दक्षिण कोरियाई सरकार इस दीवार के निर्माण को फौरन रोक दे तथा दीवार के बन गये हिस्सों को गिरा दे. *

वाम मोर्चा सरकार द्वारा बोनस निर्देश जारी

गत 10 अगस्त को राज्य श्रमिक सलाहकार बोर्ड की एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता श्रममंत्री कृष्णपद घोष ने की. इसमें 1978 के लिए बोनस के सवाल के बारे में विचार हुआ. मालिकों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के मतों को सुनने के बाद सरकार ने 9 सूत्री बोनस निर्देश घोषित किये.

इन नीतियों के तहत प्रबंधकों से कहा गया है कि (क) वे बोनस पर बातचीत करते वक्त पिछले साल वाले कायदों का पालन करें और बोनस विवादों को लचीलेपन से सुलझायें, (ख) एक ही किश्त में 8.33% न्यूनतम बोनस सभी संबद्ध लोगों को दिए जाए. (ग) पिछले साल की दर से कम कोई भी उद्योग बोनस न दे और जो अधिक दे सकते हैं—वे भी ऐसा ही करें, (घ) बीमार और कमजोर इकाइयों के मजदूरों को भी 8.33% बोनस दें, (च) आई. आर. सी. आई. द्वारा चलाई जा रही यूनिटों तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही यूनिटों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों को 8.33% बोनस मिले, (छ) न्यूनतम से अधिक बोनस जूट मजदूरों को दिया जाय, मालिक लोग इस विषय में हमदर्दी से पेश आयें, (ज) सात सितंबर तक सारे बोनस का भुगतान हो, और (झ) सभी निर्देश बदले जा सकते हैं अगर केंद्रीय सरकार इस पर कोई अध्यादेश जारी करे तो.

राज्य सरकार द्वारा इन बोनस निर्देशों के बाद भारत के राष्ट्रपति ने 1978 के लिये बोनस देने के बारे में अध्यादेश जारी कर दिया है. इस अध्यादेश के तहत न्यूनतम 8.33% और अधिकतम 20% तय किया गया है. बैंकिंग कंपनियों व औद्योगिक पुनर्निर्माण निगमों के कर्मचारियों को भी इस अध्यादेश के तहत समेट लिया गया है. *

लिपटन मजदूरों व कर्मचारियों की विजय

152 दिन हड़ताल चलाकर लिपटन टी कंपनी के मजदूरों व कर्मचारियों ने लिपटन मजदूर यूनियन के नेतृत्व में एक शानदार विजय हासिल की है. मजदूर गत 8 अप्रैल को हड़ताल पर गये. वे कंपनी द्वारा कंप्यूटर लगाये जाने, काम के मुआवजे को कम करने, स्टाकिस्ट की मांग करने के खिलाफ तथा दंडित किये गये कर्मचारियों को बहाल कराने तथा वेतनों में संशोधन की मांगों के लिए आंदोलित हुए. कंपनी ने 30 अप्रैल को वेतन बांटे बिना क्लोजर घोषित कर दिया.

16 सितंबर को एक त्रिपक्षीय बैठक में, जो लेबर कमिश्नर की पहलकदमी पर की गई, एक समझौता हुआ. इसके अंतर्गत कंपनी ने मान लिया कि वह कंप्यूटर नहीं लगायेगी. यही नहीं मजदूरों को प्रतिमाह 100 रुपये की वेतनवृद्धि भी मिलेगी. 30 चार्जशीटेड मजदूरों का केस श्रममंत्री के निर्णय के लिये छोड़ दिया गया है. अन्य लाभों में लीव ट्रेवल कंसैशन तथा 1000 रुपये तक पाने वाले कर्मचारियों के लिये ग्रेच्युटी में बढोत्तरी भी शामिल है. 18 सितंबर से मजदूर फिर काम पर वापस गये. *

हिंद मोटर्स का लाक आउट खत्म

कोलनगर में हिंदमोटर्स में 74 दिन का लाक आउट और हड़ताल 5 सितंबर को वापस ले लिये गये और फैक्ट्री के 1500 मजदूर-कर्मचारी 6 सितंबर से काम पर वापस गये. यह मजदूरों की एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि मालिकों को मजदूरों की प्रमुख मांगें माननी पड़ीं. समझौता राज्य के श्रममंत्री कृष्णपद घोष के कमरे में एक त्रिपक्षीय मीटिंग में हुआ. मजदूरों का प्रतिनिधित्व राज्य सीटू के महासचिव, मनोरंजन राय, अध्यक्ष दिनेन भट्टाचार्य तथा सीटू नेता शांति घटक ने किया.

समझौते के तहत मजदूरों को 14.25% बोनस मिलेगा. किसी भी मजदूर को दंडित नहीं किया जायेगा और प्रत्येक मजदूर को 150 रुपये अग्रिम दिया जायेगा जो पांच किश्तों में काट लिया जायेगा. 100 बदली मजदूरों को फौरन स्थायी किया जायेगा और दूसरे बदली मजदूरों के मामलों को हर छह महीने बाद आंका परखा जाता रहेगा. एक कमेटी जिसमें मजदूरों-मालिकों का एक एक प्रतिनिधि तथा लेबर कमिश्नर होगा मिलकर आठ छंटनी किये गये मजदूरों के केसों को देखेंगे.

फैक्ट्री के मजदूरों और कर्मचारियों ने 70 दिन अपने इस संघर्ष को बड़ी बहादुरी से चलाया. उन्हें अन्य ट्रेड यूनियनों जन संगठनों व अध्यापकों, औरतों व छात्र संगठनों का समर्थन भी मिला. सीटू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य जन संगठनों की ओर से हड़ताली मजदूरों के पक्ष में 29 अगस्त को कोननगर-उत्तरपाड़ा में एक सफल 'बंद' का आयोजन भीहु आ. *

बंगाल मे कैमिकल वर्कर्स की भारी विजय

काफी लंबे संघर्ष के बाद बंगाल केमिकल्स के मजदूरों ने एक भारी जीत हासिल की है. सीटू के नेतृत्व में वहां के मजदूर और कर्मचारी अपने वेतनमानो में बढ़ोत्तरी महंगाई भत्ते, वार्षिक वृद्धि, मकान किराया भत्ता, आदि को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं. 1972 के दौरान जब कांग्रेसी शासन ने राज्य में अर्ध फासिस्टी आतंक फैला रखा था, और सीटू बिल्कुल बेकार कर दी गई थी. उन दिनों इंटक की यूनियन ने कांग्रेसी श्रम मंत्री के आशीर्वाद से मालिकों के साथ एक मजदूर विरोधी समझौता किया था जिसके तहत वृद्धि और दूसरे लाभों को काट दिया गया था. 1977 के बाद जब राज्य में वाम-

मोर्चा सरकार बनी, सीटू ने मजदूरों को फिर संगठित किया और संघर्ष आरंभ कर दिया. 1977 में इस संस्थान को राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया.

छह महीने की बातचीत के बाद पिछली 30 जून को उपश्रमायुक्त के आफिस में सरकार द्वारा एक समझौता किया गया जिसमें प्रबंधकों ने अधिकांश मांगों को मान लिया था. इस समझौते के अनुसार न्यूनतम वेतन 408 रुपये से बढ़ाकर 485 रुपये किया गया, अन्य वेतनमानों में भी संशोधन किया गया. महंगाई भत्ते की दर प्रति प्वाइंट एक रुपया तीस पैसे कर दी गई जो 1960 के आधार वाली उपभोक्ता सूचकांक के 320 प्वाइंट के बाद लगेगी. मकान किराया भत्ता 15%, नगर भत्ता 6% (मूल वेतन का) कर दिया गया. टिकिट भत्ता और सालाना छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. यही नहीं अब कर्मचारी लोग (एकत्रित) छुट्टियां ले सकेंगे. इसके अलावा यदि काम करते हुए मृत्यु होती है तो उनके ऊपर निर्भर रहने वाले को नौकरी में प्राथमिकता भी मिलेगी आदि. *

जयश्री मजदूरों ने संघर्ष के जरिए 12 प्रतिशत बोनस जीता

अपने संयुक्त संघर्षों से बिड़ला जयश्री फैक्टी के मजदूरों ने प्रबंधकों को मांगें मानने के लिए मजबूर कर दिया. प्रबंधकों ने पहले पिछले साल की तरह इस वर्ष भी 9% बोनस देने का ऐलान किया किंतु सीटू समेत अन्य तीन यूनियनों के नेतृत्व में मजदूरों ने इस 9% बोनस को लेने से इनकार कर दिया और एकजुट होकर संघर्ष चलाया आखिर में प्रबंधक बातचीत करने पर मजबूर हो गये और मांगें सुलझाने के लिये तैयार हुए. समझौते के मुताबिक अब मजदूर 10% बोनस, साथ ही 2% एक्स ग्रैशिया पायेंगे. 1974 में जो चार मजदूर छांट दिये गये थे वे वापस ले लिये जायेंगे और वरीयता के मुताबिक दो सौ बदली मजदूरों को स्थाई कर दिया जायेगा.

ए. वी. बी. मजदूरों की हड़ताल जारी

दुर्गापुर स्थित ए. वी. बी. फैक्ट्री के मजदूरों की 80 दिन पुरानी हड़ताल सीटू संबद्ध एंप्लाईज यूनियन के नेतृत्व में आज भी जारी है. मजदूरों की मांगों में 1979 इंजीनियरिंग वेतन समझौता 1970 में छंटनी किये गये मजदूरों की बहाली, मकान सुविधायें आदि शामिल हैं. प्रबंधकों के जिद्दी रवैये के कारण समझौतों की सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं. राज्य के मुख्य मंत्री के दफ्तर में 31 अगस्त को एक त्रिपक्षीय बैठक भी बुलाई गई जिसमें श्रम मंत्री कृष्णपद घोष. एस. ई. बी. के चेयर मैन, एडवोकेट जनरल एस. के. आचार्य, सीटू के मोहम्मद इस्माइल तथा दूसरों ने शिरकत की. प्रबंधकों के प्रतिनिधियों ने मजदूरों की मांगों से संबंधित मुख्य मंत्री की सिफारिशों को मानने से इंकार कर दिया. बोनस के सवाल पर भी उन्होंने किसी भी समझौते पर पहुंचने से इनकार कर दिया. मजदूर तब तक अपने संघर्ष को चलाते रहेंगे जब तक प्रबंधक लोग अपने गलत एवं जिद्दी आचरण को ठीक नहीं करते और अपने संघर्ष में जीत हासिल नहीं कर लेते. *

बोनस के लिए जूट मजदूरों द्वारा सांकेतिक हड़ताल

8 सितंबर को हजारों जूट मजदूर कलकत्ता स्थित आइ. जे. एम. ए. के दफ्तर के सामने इकट्ठे हुए और 8.33% की दर से अधिक दर के बोनस की मांग के लिये एक जन प्रतिनिधि मंडल प्रबंधकों से मिला. आई. जे. एम. ए. के चेयरमैन को हजारों मजदूरों के हस्ताक्षरों वाला एक मांग पत्र भी दिया गया जो राज्य के 62 जूट मिलों के सभी मिल मैनेजरों को संयुक्त रूप में संबोधित था. इस मांग पत्र में कहा गया था कि चूंकि जूट मिल मालिकों ने पिछले साल भारी मुनाफे कमाये हैं. अतः मजदूरों को भी राज्य के बोनस संबंधी निर्देशों के अनुसार अधिक बोनस दिया जाना चाहिये जिसमें जूट मजदूरों को अधिक बोनस देने की सिफारिश की गई है. मजदूर लोग इन मांगों को मनवाने के लिये कृतसंकल्प है. यदि जूट मिल मालिक वास्तविकता नहीं पहचानते तो वे ही गलती करेंगे. 16 सितंबर को जारी हुए एक संयुक्त वक्तव्य में इंटक, ऊटक (लेनिन सरनी), एन. एफ. आई. टी. यू., एच. एम. एस., बी. एम. एस. राष्ट्रीय चटकल मजदूर यूनियन और आलइंडिया जूट टैक्सटाइल वर्कर्स फेडरेशन ने 20% न्यूनतम बोनस की मांग को लेकर 21 सितंबर को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का आह्वान किया.

तमिलनाडु...

[पृष्ठ पांच से आगे]

कानून मालिकों को गैरकानूनी लाकआउट घोषित करने या मजदूरों के विरुद्ध आक्रामक रूख अपनाने से नहीं रोकते. ऐसी चालें सिर्फ भोले लोगों को ही छल सकती हैं.

कपड़ा उद्योग का अनुभव

ये अध्यादेश तब जारी किये गये थे जब राज्य के डेढ़ लाख मजदूर हड़ताल पर थे. सरकार ने पंचफैसले को मामला सौंपा हुआ था. किंतु फिर भी मजदूरों ने इन काले अध्यादेशों को चुनौती दी और अपना संघर्ष जारी रखा जिसने मालिकों को समझौता करने पर मजबूर कर दिया. तमिलनाडु का ट्रेड यूनियन आंदोलन तब तक खामोश नहीं बैठ सकता जब तक कि अध्यादेश वापस नहीं हो जाते और इतिहास के कूड़ेदान में नहीं फेंक दिये जाते.

'दि वर्किंग क्लास'

एक प्रति की कीमत 50 पैसे
वार्षिक चंदा 6 रुपये
एजेंसी के लिए कम से कम 5 प्रतियां
लिखें : मैनेजर,
दि वर्किंग क्लास
6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : 384071

सीटू के नए प्रकाशन

'दि सीटू रिजाल्व्ज इन मद्रास'

(अंग्रेजी में)

सीटू के चौथे सम्मेलन की समीक्षा
सम्मेलन द्वारा पास किए गए प्रस्ताव

मूल्य : तीन रुपये

सम्मेलन के अन्य प्रकाशन

(अंग्रेजी व हिन्दी में उपलब्ध)

अध्यक्षीय भाषण
बी. टी. रणविदे

मूल्य : रु० 1-00

कहासचिव की जनरल रिपोर्ट
--पी. राममूर्ति

मूल्य : 75 पेसे

कार्य और संगठन की रिपोर्ट
एम. के. पंधे

मूल्य : रु० 1-00

फाइट यूनाइटिड्ली
इन दी काज आफ इंडियन
वर्किंग वूमेन
(अंग्रेजी में)

मद्रास में 9-10 अप्रैल, 1979 को हुए श्रमिक महिलाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन की रिपोर्ट

मूल्य : दो रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली-110001
और
नैशनल बुक एजेंसी (प्रा.) लि.
2, सूर्य सेन स्ट्रीट
कलकत्ता-700013

दवा उद्योग...

[पृष्ठ दो से आगे]

हैं, किस तरह वे उन दवाओं को भेजते हैं जो घटिया स्तर की या मिलावटी होती हैं और जिन्हें उनके अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया गया होता है. दंडित करने की नीति के खिलाफ राष्ट्रीयकरण के लिये और दवा उद्योग में त्रिपक्षीय वार्ता की, मांग के लिए अपने आंदोलन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इन कंपनियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं करती. उन्होंने मजदूरों व किसानों का आह्वान किया कि वे ऐसे व्यापक व मजबूत आंदोलन के जरिए इनके तथा भारतीय इजारेदारों के दवा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की मांग करें.

विश्व साम्राज्यवाद का पंजा

एम. के. पंधे जो इस कनवेंशन के मुख्य अतिथि थे, ने अपने भाषण में कहा कि कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो विश्व-साम्राज्यवाद के पंजे की तरह हैं भारतीय इजारेदारों के साथ साठ-गांठ करके भारतीय जनता का शोषण कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हालांकि हाथी कमेटी ने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की थी किंतु भारतीय सरकार उल्टे इन कंपनियों के हितों की मुहाफिज बन गई. उन्होंने कहा कि अब तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा है और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन तीसरी दुनियां के देशों में इन कंपनियों के घुसने के खिलाफ तेजी पकड़ने लगा है. ए. आई. सी. ए. पी. ई. एफ. और एफ. एम. ए. आई. को उनके मजबूत संघर्षों के लिए बधाई देते हुए उन्होंने इस उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों व भारतीय इजारेदारों के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की उनकी लड़ाई में सीटू की एकजुटता को प्रकट किया. विभिन्न संगठनों जैसे राज्य सीटू, डी. वाई. एफ. और एस. एफ. आई. के नेताओं ने भी कनवेंशन में भाषण दिया. *

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1979		
	मई	जून	जुला.
बिहार			
जमशेदपुर	331	336	341
झारिया	320	324	332
कोडर्मा	350	352	358
मोंघाइर	349	363	381
नोआमुंडी	327	333	342
गुजरात			
अहमदाबाद	331	335	341
भाव नगर	345	352	363
हरियाणा			
यमुना नगर	362	365	379
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	347	347	349
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	356	367	378
भोपाल	336	345	351
ग्वालियर	352	354	366
इंदौर	362	365	370
महाराष्ट्र			
बंबई	335	344	351
नागपुर	333	339	346
शोलापुर	349	356	363
पंजाब			
अमृतसर	352	355	366
राजस्थान			
अजमेर	339	344	356
जयपुर	365	363	371
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	333	344	351
सहारनपुर	342	343	352
वाराणसी	379	392	401
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	354	357	361
कलकत्ता	335	346	349
दार्जीलिंग	280	286	289
हावड़ा	329	332	331
जलपाइगुरी	288	293	301
रानीगंज	336	339	351
दिल्ली	374	378	388
भारत	339	345	353

(लेबर ब्यूरो, शिमला)

पश्चिम बंगाल में, इसने पी. सी. सेन के नेतृत्व में जनता के साथ अधिनायकवाद के खतरे की कब्र खोदने के लिए हाथ मिलाया. इसके रणकौशल को पूरी तरह से सफलता मिली और कांग्रेस (इं.) को सत्ता से दूर रखा गया.

अधिनायकवाद और सांप्रदायिकता को करारी हार दो

मौजूदा चुनावों में फिर से मजदूर वर्ग और कर्मचारी आंदोलन तानाशाही की चुनौती का सामना कर रहा है. अधिनायकवाद की प्रमुख शक्ति इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस (इंदिरा) है. इस गैर-जनवादी षडयंत्रकारियों के गठजोड़ को, जिसके नेतृत्व को बंसीलाल और संजयगांधी जैसे तारों पर नाज है, करारी हार देने और उखाड़ फेंकने के लिए हर कोशिश करनी होगी.

लेकिन केवल यही एक चुनौती नहीं है. जनता—जो अब आर. एस. एस.-जनसंघ का छुपा रूप है—एक और चुनौती है जिसे हराना है. इन दोनों पार्टियों को सत्ता हथियाने से कैसे दूर रखा जा सके चुनावों का मुख्य सवाल है.

मजदूर वर्ग और कर्मचारी आंदोलन समाजवाद और समाज को जड़ से बदलने के लिए कामना के द्योतक हैं, वे देश में अन्य वामपंथी और जनवादी ताकतों के साथ मिलकर सभी बुर्जुवा-जमींदार पार्टियों का वास्तविक योग्य विकल्प पेश कर सकते हैं और इसके अलावा अधिनायकवाद और सांप्रदायिक प्रतिक्रिया की ताकतों के खिलाफ लगातार लड़ सकते हैं और उन्हें हरा सकते हैं.

असमान विकास

दुर्भाग्य से, पूरे भारत में, वामपंथी और जनवादी ताकतें कमजोर हैं और इस हालत में नहीं हैं कि वे खुद ही दोनों प्रतिक्रियावादी ताकतों को हरा दें. पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में वे खुद इन दोनों चुनौतियों को मात दे सकती हैं, लेकिन यहां भी उन्हें अधिनायकवाद-विरोधी, सांप्रदायिकता-विरोधी मत जुटाने की हर कोशिश करनी चाहिए. त्रिपुरा में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व में वामपंथी ताकत अधिनायकवाद-विरोधी और सांप्रदायिकता-विरोधी ताकतों की रक्षक हैं. केरल में भी यदि वामपंथी और जनवादी ताकतें चुनाव के दौरान एकजुट हो जाएं तो कांग्रेस (इं.) और जनता को हराया जा सकता है.

देश के बाकी हिस्सों में स्थिति इस तरह की नहीं है. और फिर भी, ट्रेड यूनियन आंदोलन, मजदूर वर्ग और कर्मचारियों को कांग्रेस (इं) और जनता पार्टी को फिर से सत्ता में आने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी होगी. ट्रेड यूनियन आंदोलन को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की केंद्रीय कमेटी की जनता (एस)-कांग्रेस गठबंधन, जो आगामी चुनावों में अधिनायकवादी कांग्रेस (इं) और आर. एस. एस. की प्रभुत्ववाली जनता पार्टी की विरोधी है, को चुनने की अपील से सहमत होने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. ट्रेड यूनियन आंदोलन को इस गठबंधन को मदद करनी चाहिए और दूसरी दोनों पार्टियों को हराना तथा चुनावों को जीतना चाहिए.

ट्रेड यूनियन आंदोलन, अवश्य ही, इस राजनीतिक गठबंधन को वर्ग सीमाओं के बारे में सचेत है जैसा कि यह जनता की वर्ग सीमाओं के बारे में सचेत था जिसका इसने 1977 के चुनावों में समर्थन किया था. इस गठबंधन के अनेक नेता या तो भूतपूर्व अधिनायकवादी कांग्रेस शासन या उसके बाद जनता शासन के आवश्यक अंग थे. उनको कांग्रेस और जनता नीतियों को लागू करने के रिकार्ड से हर वामपंथी व्यक्ति, दल, संगठन और पार्टी को सतर्क रहना चाहिए कि जब यह राजनीतिक गठबंधन सत्ता में आएगा तो किस तरह की नीतियां अपनायी जानी मुमकिन हैं.

नए संबंधों को उभारने के लिए

लेकिन फौरी मुद्दा यह है कि इन दो प्रतिक्रियावादी चुनौतियों को कैसे दूर रखा जा सके, कैसे पहले इंदिरा के सत्ता में वापस आने के तरीकों को धराशायी किया जाए और फिर जनता को उसी तरह से मात दी जाए.

भविष्य के खिलाफ गारंटी कैसे दी जाए. मजदूर वर्ग और कर्मचारी जनवाद के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते अगर वे इंदिरा और जनता की चुनौतियों को हराने के साथ-साथ पार्लियामेंट में वामपंथी और जनवादी ताकतों को मजबूत नहीं करते हैं, अगर वे देश की राजनीति में मजदूर वर्ग की ताकत को और मजबूत नहीं बनाते हैं. ज्यादातर राज्यों में बुर्जुवा-जमींदार पार्टियां जनता पर प्रभाव पर एकाधिकार बनाए हुए हैं. ट्रेड यूनियन आंदोलन को ताकतों के इस आपसी संबंध को बदलने के लिए हर कोशिश करनी होगी और चुनावों के दौरान अपने हस्तक्षेप और सही रणकौशल से मजदूर वर्ग और जनता के पक्ष में एक नये संबंध को उभारने का आश्वासन देना होगा. अगर इस सवाल पर ट्रेड यूनियन आंदोलन एकजुट है, अगर यह कांग्रेस (इं) और जनता को हराने का आम कदम अपनाता है और इन दोनों ताकतों के खिलाफ सभी ताकतों का समर्थन करता है व उसे जुटाता है और साथ ही वामपंथी तथा जनवादी ताकतों की पार्लियामेंट और उसके बाहर शक्ति को मजबूत करने के लिये हर कदम उठाता है तो यह चुनाव के बाद की चुनौतियों का सामना करने में अच्छी तरह से तैयार होगा.

इसका मतलब यह है कि जहां वामपंथी और जनवादी ताकतें प्रबल हैं, जहां वे प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ प्रमुख चुनौती का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में, वहां समूचे ट्रेड यूनियन और कर्मचारी आंदोलन को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व में वाममोर्चे

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

बोनस के न मिलने पर नवंबर में हड़ताल

ए. आई. आर. एफ. की वर्किंग कमेटी ने 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला लिया कि अगर रेलवे कर्मचारियों को बोनस और अन्य मांगों जैसे वेतन में समानता आदि पर समझौता नहीं हुआ तो नवंबर में वे किसी समय हड़ताल करेंगे. ए. आई. आर. एफ. के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री से मिले थे जिन्होंने इस सिलसिले में रेलवे मंत्री से बातचीत करने की सलाह दी थी. इस मसले पर गौर करने के लिए केबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई है. ए. आई. आर. एफ. की वर्किंग कमेटी ने हड़ताल के लिए रेल श्रमिक एकता को जल्द से जल्द और व्यापक बनाने का फैसला लिया है.

पता चला है कि विभिन्न यूनियनों के साथ 24 सितंबर को सलाह मशविरा किया गया था. किन्तु एल.आर.एस.ए. के नेता बीमार होने की वजह से इसमें शामिल न हो सके थे और इसलिए ऐसी बातचीत के लिए एक मीटिंग अक्तूबर के पहले हफ्ते में रखी गई है. समझा जाता है कि एन.एफ.आई.आर. को भी शायद इसमें बुलाया जाए ताकि रेलवे कर्मचारियों में संपूर्ण एकता कायम की जा सके. *

दिल्ली एल.आर.एस.ए. ने विजय हासिल की

दिल्ली डिवीजन (उ.रे.) के लोको रनिंग स्टाफ के साथ माइलेज भत्ते के हिसाब में भेदभाव बरता जा रहा था. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा पिछली मार्च को दिए गए फैसलों को लागू नहीं किया गया था. इसीलिए एल. आर. एस. ए. की दिल्ली शाखा ने आंदोलन पर जाने का नोटिस दिया, जिसने अधिकारियों को बहुत सी मांगे मान लेने के लिए मजबूर कर दिया. *

रेल सेवाओं को रद्द करने का एल.आर.एस.ए. द्वारा विरोध

एल. आर. एस. ए. के महासचिव एस. के. घर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में रेलवे अधिकारियों की, यात्रीगाड़ी सेवाओं को कोयले की कमी के कारण रद्द करने की कड़ी आलोचना की. खासकर इसलिए क्योंकि इनमें से कुछ गाड़ियों को डीजल या बिजली से चलाया जा सकता था. यह नोट करना चाहिए कि गाड़ियां इस तरह रद्द करने से लोको रनिंग स्टाफ के वेतन पर असर पड़ता है. चूंकि वे कार्यहीन हो जाते हैं. *

मीटिंग, कनवेंशन

सियालदह डिवीजन की ज्वाइंट काउंसिल आफ एक्शन की रानाघाट शाखा, ने 5 सितंबर को अपनी सालाना कानफ्रेंस आयोजित की जिसकी अध्यक्षता पी. के. गुप्ता दत्ता ने की. नृसिंह चक्रवर्ती ने कानफ्रेंस का उद्घाटन किया. ब्रजेश चौधरी, सचिव, ने रिपोर्ट पेश की जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया. *

एस. ई. आर. एस. यू. की सांताग्राची शाखा ने यात्रियों तथा रेलवे कर्मचारियों की 4 सितंबर को संयुक्त कनवेंशन आयोजित की जिसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम मंत्री कृष्णपद घोष ने किया. अन्य नेताओं सहित ए.आई.आर.एफ. की वर्किंग कमेटी के सदस्य के. एम. भद्र ने कनवेंशन को संबोधित किया. *

[शेष पृष्ठ पंद्रह पर]

रेलवे कर्मचारियों की बोनस की मांग का सीटू द्वारा समर्थन

सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 18 सितंबर को निम्नलिखित बयान जारी किया :

सीटू रेलवे कर्मचारियों की बोनस सहित अन्य जायज मांगों, जो रेलवे कर्मचारियों के दिमागों को लंबे अर्से से आंदोलित कर रही हैं, पर समझौता करने में देरी होने पर गहरी चिंता व्यक्त करती है. जनता सरकार, जिसमें मई 1974 के ऐतिहासिक संघर्ष के कुछ नेता केबिनेट में भी शामिल थे, हालांकि सैद्धांतिक रूप से समझौता वार्ता के लिए तैयार हो गई थी किंतु बुनियादी मांगों को तय करने के लिए उसने पिछले ढाई सालों से कुछ नहीं किया था. ऐसा लगता है कि स्थिति अब संकट की तरफ बढ़ती जा रही है क्योंकि ए. आई. आर. एफ. ने मतदान द्वारा हड़ताल करने का फैसला ले लिया है तथा हड़ताली कार्रवाई करने के इरादे की घोषणा कर दी है. यह अच्छी बात है कि ए. आई. आर. एफ. ने व्यापक एकता कायम करने का निर्णय लिया है जो वक्त की जरूरत है.

सीटू रेलवे मजदूरों को बोनस देने तथा वेतन में बराबरी की मांग वगैरह का पूरा समर्थन करती है तथा सरकार को चेतावनी देती है कि रेलवे कर्मचारियों का धर्य छूटा जा रहा है और संकट को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द समझौता किया जाना चाहिए. *

शोक समाचार

सी० आर० दत्त हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी यूनियन, भिलाई के उपाध्यक्ष तथा सीटू की मध्य-प्रदेश राज्य कमेटी के सदस्य ने 20 सितंबर को वेल्लोर के अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली. वे मस्तिष्क के आपरेशन के संबंध में एक महीने से हस्पताल में थे. उनका वेल्लोर में दाह संस्कार किया गया.

सीटू तथा सीटू मजदूर हिंदुस्तान स्टील कर्मचारी यूनियन, सीटू की म० प्र० राज्य कमेटी तथा उनके परिवार के शोकग्रस्त सदस्यों को गहरी संवेदना व्यक्त करती है. *

बी. राम सशैयाह, साउथ सेंट्रल रेलवे एंप्लाईज यूनियन (सीटू) के कोषाध्यक्ष ने विजयवाड़ा के रेलवे अस्पताल में 29 अगस्त को अंतिम सांस ली. सीटू ने उनके शोकग्रस्त परिवार को अपनी संवेदना भेजी है. *

रेल समाचार

[पृष्ठ चौदह से आगे]

19 सितंबर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल की वर्षगांठ के मौके पर ईस्टर्न रेलवेमेंज यूनियन ने इस साल 19 सितंबर को सुबोध मल्लिक स्क्वेयर में एक विशाल जन सभा आयोजित की जिसमें विमल डे, कनाई बैनर्जी और अन्य नेताओं ने भाषण दिये. इस दिन ही पूर्वी रेलवे में एन. सी. सी. आर. एस. को औपचारिक रूप से पुनः शुरू किया गया था. *

पठानकोट के रेलवे मजदूरों ने 19 सितंबर को शहीद दिवस मनाया. इसमें वहां की ट्रेड यूनियनों, सरकारी अध्यापकों, रोडवेज और सीटू इत्यादि सभी ने हिस्सा लिया. 1969 से इस उत्सव को मनाया जा रहा था. खुले अधिवेशन को एन. आर. एम. यू. के सिद्दीकी और नृसिंह चक्रवर्ती ने संबोधित किया. एटक के कुछ स्थानीय नेताओं ने इसे इसे अलग से मना कर वैमनस्य के चिह्न छोड़ दिए. *

बीड़ी सिगार वर्कर्स कमेटी के फैसले

आल इंडिया बीड़ी और सिगार वर्कर्स कमेटी की 30-31 अगस्त को बंगलौर में बैठक हुई. एस. सूर्यनारायण राव ने इसकी अध्यक्षता की. केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सदस्यों और केंद्र से विमला रणदिवे ने भाग लिया. सी. कन्नन, सचिव, द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में बीड़ी उद्योग के सामने आने वाली मौजूदा समस्याओं जैसे कि केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में छूट जो पहले तम्बाकू पर लगती थी तथा अब सिर्फ बीड़ी पर ही लगाई जा रही है. सिर्फ लेबल बीड़ियों पर लेवी के थोपे जाने से बाजार में टैक्स को पूरी तरह से बचा कर जाली बीड़ियों की भरमार लग गई है.

बीड़ी मजदूर कल्याण योजना की फिर से जांच पड़ताल करने पर यह पाया गया कि यह योजना सिर्फ कुछ ही राज्यों जैसे केरल और कर्नाटक में लागू है तथा वह भी संतोषजनक ढंग से नहीं. केंद्रीय सरकार द्वारा कल्याण राशि योजना के लिए कर लगाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है. बीड़ी और सिगार एक्ट को ज्यादातर राज्यों में लागू नहीं किया जा रहा है जिसके नतीजतन घरों में काम करने वाले मजदूरों को एक्ट के तहत आने वाले लाभों से पूरी तरह वंचित किया गया है. हर जगह फैली ठेका प्रथा द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है. एक समान वेतन नीति के अभाव में राज्यों तथा एक राज्य में एक जगह से दूसरी जगह में वेतन में विभिन्नता है, महिला तथा पुरुष बीड़ी मजदूरों की वेतन दरों में भारी अंतर है.

कर्नाटक और केरल के सदस्यों ने यह बताया कि इन दोनों राज्यों में बीड़ी मजदूर आंदोलन की ताकत के आधार पर रु. 6·50 से रुपये 10·75 प्रति 1000 बीड़ी प्राप्त कर रहे हैं. सीटू के तहत मजदूर अपनी एकता के कारण वेतन सहित छुट्टी, मकान के लिए कर्ज, अपने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, प्रसूति छुट्टी, बोनस, मृत्यु सहायता कोष, चल चिकित्सालय गाड़ी वगैरह प्राप्त कर सके हैं. अपनी मांगें मनवाने तथा उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने में केरल में को-आपरेटिवों ने मजदूरों की मदद जरूर की है. यह आश्चर्य की बात है कि किसी भी राज्य में सलाहकार समितियों का गठन नहीं किया गया है. हालांकि इनका गठन बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था.

विचार विमर्श करने के बाद कमेटी ने केंद्रीय सरकार से आग्रह किया कि कल्याण कोष योजना के सुचारू कार्य के लिए ठेका प्रथा को खत्म करे. बैठक ने सभी बीड़ी मजदूरों से 8 से 9 रुपये प्रति हजार बीड़ी वेतन, कम काम या बिना काम के भी पूरे वेतन, 20 प्रतिशत बोनस, वेतन में औसत के नाम पर कटौती को बंद करने तथा हफ्ते में छः दिन पूरे काम के लिए अभियान शुरू करने का आह्वान किया.

इन मांगों को हासिल करने के लिए कमेटी ने 17 अक्तूबर को जलसे, जुलूस, सभाएं, प्रदर्शन आदि करके 'मांग दिवस' मनाने का आह्वान किया. कमेटी ने केरल में नवंबर के महीने में होने वाली अखिल भारतीय कानफ्रेंस को संसदीय चुनावों की वजह से स्थगित करने का भी फैसला लिया. *

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर पचास पैसे

वार्षिक चंदा छः रुपये

एजेंसी के लिए कम से कम पांच प्रतियां

मिलने का पता

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड,

नई दिल्ली-110001

सीटू की आई. एल. ओ. की शिकायत

[पृष्ठ पांच का शेष]

नंदलाल ने इन सभी आरोपों को झूठा साबित किया और यह भी साबित किया कि वह कोयला श्रमिक संघ (सीटू) का एक लोकप्रिय नेता है. किंतु अदालती मजिस्ट्रेट ने बिना किसी सबूत के निर्वासन के आदेश जारी कर दिये. इस आदेश की वजह से नंदलाल न केवल अपनी नौकरी से वंचित हो गया है बल्कि उसका परिवार भी भूखों मरने को मजबूर है.

सीटू के विचार में यह आदेश उस क्षेत्र के कोयला खानों के मजदूरों के बीच ट्रेड यूनियन कार्य करने को रोकने के इरादे से किया गया है. यही नहीं म. प्र. के मुख्यमंत्री ने जाहिर तौर पर यह कहा है कि वे सीटू यूनियनों को म. प्र. में फैलने नहीं देंगे. इस तरह मजदूरों को संघ बनाने की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा रही है.

सीटू ने मध्य प्रदेश में हो रहे इन ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले के खिलाफ 'कमेटी आफ फ्रीडम आफ एसोसिएशन' इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन से शिकायत की है कि वह भारत सरकार से दरियाफ्त करे तथा ऐसे कदम उठाये जिससे नंदलाल अपनी जगह काम पर वापस आ सके और ट्रेड यूनियनका काम कर सके. *

एजेंटों से

एजेंटों से निवेदन है कि वे हर महीने बिल चुकता करें. ऐसा न करने से **सीटू मजदूर** के प्रबंध में हमें काफी दिक्कतें आती हैं. इसके अलावा मनीआर्डर भेजते समय उसके नीचे की स्लिप, जो संदेश के लिए होती है, पर भी अपना पूरा पता लिखें.

मैनेजर

मजदूर वर्ग की जिम्मेदारी

[पृष्ठ तेरह से आगे]

के उम्मीदवारों की पूरी सफलता का आश्वासन देना होगा.

दूसरे राज्यों में इसको जनता (एस)-कांग्रेस गठबंधन का दो चुनौतियों को धराशायी करने के लिए समर्थन करते हुए मजदूर वर्ग और वामपंथी ताकतों के उम्मीदवारों का लोकसभा में जहां तक मुमकिन हो वहां तक प्रबल प्रतिनिधित्व दिलाने में हर कोशिश करनी होगी. ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकजुट ताकत इतनी है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसके मशविरे को नजरंदाज नहीं कर सकती. आने वाले दिनों में इस ताकत को उन इलाकों में इस्तेमाल करना होगा जहां वामपंथी और जनवादी ताकतें कमजोर हैं.

समाज के बुनियादी बदलाव के लिए

इसके अलावा, एकजुट ट्रेड यूनियन आंदोलन को मजदूर वर्ग और जनता को सारी सच्चाई बतानी होगी. इसे उनको बताना होगा कि समाज के बुनियादी बदलाब के लिए दृढ़ निश्चय के बिना और भूमि व पूंजी में निजी स्वार्थों पर निडर और ताकतवर हमले के बिना तानाशाही की चुनौती, गरीबी और बेरोजगारी की चुनौती के साथ निबटा नहीं जा सकता. बाकी सब चीजें हालात के साथ फूहड़ की तरह काम कर रही हैं. एकजुट ट्रेड यूनियन आंदोलन अपने बदलावी कार्यक्रम के साथ मजदूर वर्ग और शहरों को झकझोरने में कामयाब होगा और ताकतों के आपसी संबंध को बदलने में मदद करेगा.

आगामी चुनाव भारत के सामाजिक ढांचे के संकट पर जोर देता है. जनता बहुमत का टूट जाना परित्याग या दलबदल का नतीजा नहीं था, यह संकट के दौरान वर्ग नीतियों के दिवालियेपन के कारण था. कोई भी बुर्जुवा—जमींदार पार्टी पार्लियामेंट या राज्य विधान सभाओं में न तो एकता बनाए रख सकती है और न ही बहुमत बरकरार रख सकती है. राजनीतक अस्थिरता ने अब केंद्र पर धावा बोल दिया है. यह फिर से राज्यों की ओर भी फैल रहा है. लेकिन राजनीतिक अस्थिरता तानाशाही की ओर ले जाती है जैसा कि पाकिस्तान और बंगला देश की मिसालें बताती हैं. जहां मजदूर वर्ग आंदोलन अपने हस्तक्षेप से अस्थिरता की चुनौती का सामना करने में समर्थ नहीं है वहां लोग दास बन जाते हैं. इसलिए भारत के मजदूर वर्ग और कर्मचारियों को अपने कंधों पर आने वाली महान जिम्मेदारियों को समझना होगा.

इस लड़ाई में, अधिनायकवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने और वामपंथ के इर्द-गिर्द होने के वास्ते जनता को प्रेरित करने के लिए भारत का मजदूर धर्ग और वामपंथी ताकतें पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में हमारी उपलब्धियों के महान हथियार से सुसज्जित हैं. इस हथियार का पूरी तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि जनता एक बुर्जुवा-जमींदार सरकार और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व में वाम-मोर्चा सरकार के काम करने के तौर तरीकों में फर्क भली-भांति जाने. *

संपादक मंडल

बी टी रणदिवे (अध्यक्ष)

पी राममूर्ति मनोरंजन राय

निरेन घोष सुधिन कुमार

एम के पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 97-98, डीएसआईडीसी कम्पलैक्स, ओखला, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित